Guarantee for loans by KVIC

1691. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of the State Governments which have agreed to provide guarantee for loans by the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) from the Consortium of Bank Credit; and

(b) what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The issue regarding the State Government Guarantee to enable State KVIBs to avail of consortium credit had been discussed in the meeting of State Industry Ministers held on 14th June, 1995. In the said conference, most of the States had shown their willingness for providing the required guarantee. During the recent discussions held by KVIC with State KVI Boards for finalising their Budgets, representatives of KVI Boards from most of the States have conveved willingness of their State Governments to provide such guarantees. The required format for taking the guarantee has been finalished by KVIC and is being sent to State KVI Boards for obtaining State Government guarantee.

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में "कापार्ट" द्वारा ऋण दिया जाना

1692. **श्री राजूभाई ए. परमार :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से जून 1995 तक की अवधि के दौरान गुजरात, विशेषकर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में, "कापार्ट" द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए दिए गये ऋणों और अनुदानों का ब्यौरा क्या है और ये संगठन कौन-कौन से है और उनके द्वारा आंरभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है,

(ख)इन संगठनों ने कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया है,

(ग) क्या इन संगठनों द्वार आंरभ किए गए कार्यों का कोई मूल्यांकन कराया गया है / कराया जाएगा,

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रायल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जवाहर रोजगार योजना

1693. **श्री सुंदर सिंह भंडारी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में जवाहर रोजगार योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है,

(ख) सरकार ने इस कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों व पर्याप्त निगरानी के विषयों पर अभी तक कौन-कौन से सफल प्रयोग किये हैं, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित कुल राशि में से प्रति वर्ष कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तभाई एच.पटेल) : (क) जवाहर रोजगार योजना, जिसे 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है इसके आंरभ होने से ही सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य स्तर के संगठनों को शामिल करते हुए जिला/खंड/ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में शामिल सरकारी और गैर सरकारी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है । राज्य सरकारों को फील्ड स्तर पर जवाहर रोजगार योजना की देख-रेख करने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु भी कार्यशालाएं/कार्यक्रम आयोजित करने हैं । भारत सरकार भी काग्रक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न संचलनात्मक ब्यौरों/कठिनाइयों का पता लगाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल परियोजना निदेशकों की प्रत्येक वर्ष कार्यशालाएं आयोजित करती है । जवाहर रोजगार योजना के निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है और मासिक,तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों की मार्फत इसकी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर निगरानी की जा रही है । इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय जिला, उप प्रभाग और खंड स्तर के अधिकारी कार्यस्थलों का दौरा करके कार्यक्रम के सभी

पहलुओं की कड़ी निगरानी करते हैं । प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विकास हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति भी जवाहर रोजगार योजना सहित सभी ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है । जवाहर रोजगार योजना सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 से क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उप सचिव और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी को एक अथवा दो राज्य आवंटित किये गए है । इन अधिकारियों को उन्हें आबंटित राज्य/राज्यों का दौरा कार्य के कार्यान्वयन संबधी जानकारी देनी होती है । ग्रामीण गरीबों और बेरोजगार का अधिक अनुपात वाले राज्यों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए क्षेत्र अधिकारी योजना में 1.1.1993 से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग, योजना आयोग के अधिकारियों को भी शामिल करके इसे और सुदृढ़ बनाया गया है।

भारत सरकार ने जवाहर योजना के विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव का जायजा लेने के लिए स्वतंत्र संस्थाओं /संगठनों की मार्फत कार्यक्रम का एक समवर्ती मूल्याकंन भी करवाया है । सरकार द्वारा अधिकारियों, गैर सरकारी लोगों के प्रशिक्षण और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किए गए उपाय संतोषजनक समझे गए हैं ।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के 18400 करोड़ रूपये कुल आवंटन मे से राज्यों और अन्य एजेंसियों को योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज के वर्ष-वार निम्नलिखित है :-

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	केन्द्रीय रिलीज
1992-93	2546.00
1993-94	3306.00
1994-95	3542.89
1995-96 (बजटबद्ध)	3862.00

Collection of genetic samples by MNCs

1194. SHRIMATI KAMLA SINHA Will the Minister of INDUSTRY b pleased to state:

(a) whether it is a fact tha Multinational Companies are collecting genetic DNA samples from remote tribal and remote Island population;

(b) whether it is also a fact tha handful of MNC Gene Companies an rushing to privatise human genes an< their products; and

(c) if so, what steps Government an taking in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) The Government has no information in this regard.

(b) and (c) Living organisms are not patentable under the provisions of the Patents Act, 1970.

Achivement of leaner and meaner army

1695. SHRI PRAGADA KOTAIAH:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINSTER be pleased to state:

(a) whether the army has the long term objective of a 'leaner and meaner Army';

(b) if so, what does it mean; and

(c) what steps are being taken to achieve this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) The Government are making all efforts to improve overall combat effectiveness of the Army by optimum and cost effective utilisation of the resources. Teeth to Tail ratio in the Army has substantially improved in last several years. Necessary steps have been taken to enhance combat potential within the manpower ceiling of the Army.